दृष्टि The Vision

करेंट अफेयर्स झारखंड

सितंबर (संग्रह)

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009

फोन: 8750187501

ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

झारखंड **5**

- सीसीएल (CCL) की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर 5
- नौ सड़कों के निर्माण को मंज़ूरी 5
- 'स्पेक्ट्रल एन्हांसमेंट' (एसपीई) 5
- मनोज कुमार सिंह को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार 6
- पहला अनुपूरक बजट 6
- मुख्यमंत्री ने 2 पॉवर ग्रिड की आधारशिला रखी 7
- IIT Dhanbad को इंजीनियरिंग संस्थानों में देश में 11वाँ स्थान 7
- सहायक अभियंताओं की नियुक्ति में सवर्णों को मिलेगा आरक्षण 8
- 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप, 2021 8
- गिरिडीह ज़िले को सोलर सिटी बनाने का प्लान 8

नोट :

- 22 ज़िलों के पुलिस थानों में ई-एफआईआर को कैबिनेट की मंज़ूरी 9
- सिंहभूम के गुड़ाबांदा में मिला 'पन्ना' 9
- सोहराई व कोहबर चित्रकला 9
- डालमा हिल में 'पाइथन' का संरक्षण 10
- कोल इंडिया लिमिटेड का पहला व्यावसायिक कोल बेड मीथेन निष्कर्षण 10
- झारखंड की सभी पंचायतों में जेनरिक मेडिकल स्टोर्स खोलने का प्रस्ताव 11
- सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना 11
- जेएसएलपीएस (JSLPS) द्वारा पीवीटीजी (PVTGs) जनजातियों के विकास की पहल 12
- झारखंड के 9 दिव्यांगों को हुनरबाज़ पुरस्कार 12
- प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिये आदिवासी भाषाओं में पाठ 12
- मुख्यमंत्री ने 'वैक्सीन एक्सप्रेस' वाहनों को दिखाई हरी झंडी 13
- झारखंड को गोवा से मिला ट्रेन कनेक्शन 14

नोट :

नोट :

झारखंड

सीसीएल (CCL) की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर

चर्चा में क्यों ?

- 31 अगस्त, 2021 को हज़ारीबाग के बड़कागाँव की रहने वाली आकांक्षा कुमारी सीसीएल की पहली महिला माइनिंग इंजीनियर बनी हैं।

प्रमुख बिंदु

- सीसीएल के चार दशक के इतिहास में यह पहली बार है जब एक महिला माइनिंग इंजीनियर ने अपना योगदान दिया है। आकांक्षा ने नॉर्थ कर्णपुरा क्षेत्र के चूरी भूमिगत खदान में ड्यूटी ज़्वाइन की।
- आकांक्षा कोल इंडिया की दूसरी और भूमिगत खदान में योगदान देने वाली पहली महिला माइनिंग इंजीनियर हैं। उन्होंने अपने इंजीनियरिंग कोर्स में माइनिंग को चुनकर न सिर्फ इस भ्रांति को तोड़ा है कि खनन क्षेत्र सिर्फ पुरुषों के लिये है, बल्कि अपने जैसे और भी महत्त्वाकांक्षी छात्राओं को प्रेरित किया है।
- उल्लेखनीय है कि आकांक्षा के पिता अशोक कुमार बड़कागाँव के एक स्कूल में शिक्षक हैं और माता मालती कुमारी गृहिणी हैं। इन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई नवोदय विद्यालय से की है।
- ज्ञातव्य है कि आकांक्षा कुमारी ने 2018 में बीआईटी (सिंदरी) धनबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। कोल इंडिया में अपना योगदान देने से पहले उन्होंने तीन वर्ष तक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की राजस्थान स्थित बल्लानरिया खदान में काम किया।

नौ सड़कों के निर्माण को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2021 को पलामू के सांसद वी.डी. राम ने कहा कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने पलामू और गढ़वा ज़िलों के वामपंथी-चरमपंथी प्रभावित क्षेत्रों के लिये अपनी सड़क संपर्क परियोजना के तहत नौ सड़कों और आठ लॉजिस्टिक सपोर्ट ब्रिज को मंज़ूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- उन्होंने कहा कि नौ सड़कों में से दो गढ़वा ज़िले में तथा सात पलामू में हैं, जबकि सभी आठ लॉजिस्टिक सपोर्ट ब्रिज पलामू ज़िले में साथी, सापी, सतबहिनी और पत्थलबाजा नदियों पर हैं।
- उल्लेखनीय है कि इन सड़कों और लॉजिस्टिक सपोर्ट ब्रिज को एमएचए द्वारा तभी मंज़ूरी दी जाती है, जब संबंधित ज़िला पुलिस अधीक्षक (एसपी) उग्रवाद के खिलाफ लड़ाई में इसके रणनीतिक मूल्य पर इसके लिये सिफारिश करते हैं।

'स्पेक्ट्रल एन्हांसमेंट' (एसपीई)

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने 'स्पेक्ट्रल एन्हांसमेंट' (एसपीई) नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है, जो कोयला अन्वेषण प्रक्रिया के दौरान भूकंपीय सर्वेक्षण का उपयोग करके पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे पतले कोयले की परतों की पहचान करने और कोयला संसाधनों के आकलन में सुधार करने में मदद करेगा।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सीआईएल के अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) शाखा सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) ने गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट (जीईआरएमआई) के सहयोग से अपनी तरह का यह पहला सॉफ्टवेयर विकसित किया है।
- कोयला संसाधन अन्वेषण के लिये वर्तमान भूकंपीय सर्वेक्षण तकनीकों में पृथ्वी के नीचे पतले कोयले की परतों की पहचान करने की सीमाएँ हैं। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से अब भूकंपीय संकेतों के समाधान को बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे कोयले की सबसे पतली परत का चित्रण होता है।
- यह 'मेड इन इंडिया' सॉफ्टवेयर कोयले की खोज़ के समय और लागत को बचाने में भी मदद करेगा, जिससे कोयला उत्पादन में 'आत्मनिर्भर भारत' के मिशन को बढ़ावा मिलेगा।
- गौरतलब है कि भारत के कुल कोयला उत्पादन में सीआईएल की हिस्सेदारी 80 फीसदी है।

मनोज कुमार सिंह को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 5 सितंबर, 2021 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वर्चुअल माध्यम से राज्य के हिंदुस्तान मित्र मंडल स्कूल, गोलमुरी के शिक्षक मनोज कुमार सिंह को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, 2021 से सम्मानित किया।

प्रमुख बिंदु

- मनोज कुमार सिंह इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के झारखंड से एकमात्र प्राप्तकर्त्ता हैं। पुरस्कार में उन्हें एक पदक, एक प्रमाण-पत्र और 50,000 रुपए दिये गए।
- मूलरूप से बिहार के गया के रहने वाले मनोज कुमार सिंह ने कक्षा एक से आठ तक के लिये जेसीईआरटी हेतु गणित की किताब तैयार की थी तथा कोविड के दौरान स्कूल बंद रहने के बाद भी बच्चों को गणित पढ़ाते थे।
- उन्हें जटिल गणितीय अवधारणाओं को नवोन्मेषी व्यावहारिक और कला-आधारित शिक्षाशास्त्र के माध्यम से पढ़ाने के लिये जाना जाता है, जो ज़्यादातर कक्षा के बाहर किया जाता है। वह अपने YouTube चैनल 'क्रिएटिव लर्निंग विथ मनोज' के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षण भी संचालित करते हैं।
- वह झारखंड शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (जेसीईआरटी) की ई-कंटेंट डेवलपर टीम का भी हिस्सा हैं, जिन्होंने डिजी स्कूल ऐप के माध्यम से महामारी के दौरान गणित के लिये ऑनलाइन सामग्री तैयार की है।
- गौरतलब है कि वर्ष 1958 में स्थापित, 'राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार' केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के मेधावी शिक्षकों को सार्वजनिक मान्यता देने के लिये हर साल शिक्षक दिवस पर प्रदान किया जाता है।
- इस पुरस्कार में एक रजत पदक, प्रमाण-पत्र और 50,000 रुपए दिये जाते हैं।

पहला अनुपूरक बजट

चर्चा में क्यों ?

- 6 सितंबर, 2021 को झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2021-22 का पहला अनुपूरक बजट पेश किया।

प्रमुख बिंदु

- राज्य के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 4684.93 करोड़ रुपए का बजट सदन के पटल पर प्रस्तुत किया।
- इस बजट में सबसे ज़्यादा ऊर्जा विभाग को 1786.05 करोड़ रुपए दिये गए हैं। वहीं, खान विभाग को 1000.30 करोड़, आपदा प्रबंधन को 337.32 करोड़, कृषि विभाग को 324.75 करोड़ और स्वास्थ्य विभाग को 279.30 करोड़ रुपए आवंटित किये गए हैं।

नोट :

मुख्यमंत्री ने 2 पॉवर ग्रिड की आधारशिला रखी

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सचिवालय में ऊर्जा विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से गढ़वा ज़िले की भगोडीह में स्थापित 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन मेराल का उद्घाटन किया और 132/33 केवी ग्रिड सबस्टेशन नगर अंतरी (भवनाथपुर) और ग्रिड सब स्टेशन छतरपुर की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि इस ग्रिड सब स्टेशन मेराल की स्थापना से गढ़वा ज़िले के मकरी, पंडरिया, बुका, गरदा, सरैया, अरसली आदि क्षेत्रों को लाभ होगा।
- अब इन इलाकों के उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज की समस्या से राहत मिलेगी तथा यहाँ के व्यवसायियों, स्कूलों और अन्य संस्थानों समेत सभी लोगों को बिजली से जुड़ी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि पलामू मंडल में भविष्य में बिजली की मांग को देखते हुए नगर अंतरी (भवनाथपुर) और छतरपुर में 132/33 केवी ग्रिड सब-स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। आने वाले 24 महीनों में दोनों पॉवर सबस्टेशन ग्रिड बनकर तैयार हो जाएंगे।
- उन्होंने कहा कि छतरपुर में बनने वाले बिजली सबस्टेशन ग्रिड में पहली बार जीआईएस (गैस इंसुलेटेड स्विचगियर) तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पॉवर ट्रांसमिशन में गड़बड़ी कम देखने को मिलेगी।

IIT Dhanbad को इंजीनियरिंग संस्थानों में देश में 11वाँ स्थान

चर्चा में क्यों ?

- 9 सितंबर, 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ)-2021 में आईआईटी, धनबाद को 11वां स्थान मिला है।

प्रमुख बिंदु

- इसके साथ ही इंजीनियरिंग संस्थानों की श्रेणी में बीआईटी मेसरा को 46वाँ तथा एनआईटी जमशेदपुर को 86वाँ स्थान प्राप्त हुआ है।
- आईएसएम की रैंकिंग में और सुधार हुआ है। देश के टॉप 100 इंजीनियरिंग कॉलेजों में यह संस्थान पिछले साल 12वें स्थान पर था, जो इस बार 11वें स्थान पर पहुँच गया है। वहीं, बीआईटी मेसरा की रैंकिंग में गिरावट का सिलसिला जारी है। इंजीनियरिंग कॉलेजों की श्रेणी में इसे इस बार 46वाँ स्थान मिला है। पिछले साल इसे देश भर में 38वाँ स्थान मिला था।
- वहीं, एनआईटी, जमशेदपुर की रैंकिंग में भी गिरावट आई है। यह 79वें स्थान से खिसककर 86वें स्थान पर पहुँच गई है।
- नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क में इस बार भी देश के टॉप 100 कॉलेजों में झारखंड का एक भी कॉलेज स्थान नहीं बना पाया है।
- मेडिकल कॉलेजों, डेंटल कॉलेजों, विधि कॉलेजों तथा रिसर्च की श्रेणी में झारखंड का एक भी संस्थान अपना स्थान नहीं बना सका है।
- विश्वविद्यालयों की श्रेणी में देश भर के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में झारखंड से एकमात्र बीआईटी मेसरा ने स्थान बनाया है, हालाँकि इसकी रैंकिंग भी 66वें से गिरकर 86वें स्थान पर पहुँच गई है।
- प्रबंधन संस्थानों की श्रेणी में टॉप 100 संस्थानों में चार झारखंड के हैं। हालाँकि, जमशेदपुर के एक्सएलआरआई को छोड़कर तीन संस्थानों की रैंकिंग में गिरावट आई है। एक्सएलआरआई देश भर में आठवें, आईआईएम, राँची 21वें, आईएसएम धनबाद 30वें तथा बीआईटी 70वें स्थान पर है।
- आईआईएम, राँची की रैंकिंग में गिरावट आई है। इसी तरह, ओवरआल आईआईटी, धनबाद 26वें स्थान पर है। बीआईटी मेसरा को इस बार इसमें स्थान नहीं मिला है। पिछले साल यह 85वें स्थान पर था है। आर्किटेक्चर संस्थानों की श्रेणी में बीआईटी को टॉप 50 में 14वाँ स्थान मिला है।
- उल्लेखनीय है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा नवंबर 2015 में शुरू किये गए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग प्रेमवर्क का यह छठा संस्करण है।

नोट :

सहायक अभियंताओं की नियुक्ति में सवर्णों को मिलेगा आरक्षण

चर्चा में क्यों ?

- 10 सितंबर, 2021 को झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंताओं की नियुक्ति में सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के लिये एकलपीठ के आदेश को रद्द करते हुए आरक्षण जारी रखने का आदेश दिया है।

प्रमुख बिंदु:

- जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सरकार की अपील याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि नियुक्ति प्रक्रिया जिस दिन से शुरू होती है, उसी समय का नियम लागू होता है।
- पहले की रिक्तियाँ भी नए नियम के तहत भरी जाती हैं। अदालत ने सरकार के निर्णय को सही ठहराया और जेपीएससी को नियुक्ति प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया।
- उल्लेखनीय है कि अदालत ने 23 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
- ज्ञातव्य है कि जेपीएससी ने सहायक अभियंताओं के कुल 634 पद पर नियुक्ति के लिये 2019 में विज्ञापन निकाला था। इस नियुक्ति में वर्ष 2015 से 2019 तक की रिक्तियाँ शामिल की गई थीं और सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा था।
- सरकार के इस आदेश को रंजीत कुमार सिंह और अन्य ने एकलपीठ में चुनौती दी थी। इसमें कहा गया था कि इस नियुत्ति में 2015 से 2019 तक की रित्तियां शामिल हैं। ऐसे में सवर्णों को दस प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता, क्योंकि सरकार ने वर्ष 2019 में सवर्णों को आरक्षण देने का निर्णय लिया है।
- गौरतलब है कि 23 फरवरी, 2019 को सरकार ने सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण देने का निर्णय लियाद्य 21 जनवरी, 2020 को एकलपीठ ने नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी फिर 6 मार्च को सरकार ने एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अपील की और 10 सितंबर को खंडपीठ ने फैसला सुनाया।

11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप, 2021

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में हॉकी इंडिया ने झारखंड के सिमडेगा ज़िले में 11वीं जूनियर राष्ट्रीय महिला हॉकी चैंपियनशिप 2021 के आयोजन हेतु तारीखों की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- हॉकी झारखंड के महासचिव विजय शंकर सिंह के अनुसार चैंपियनशिप का उद्घाटन 20 अक्तूबर को तथा समापन 30 अक्तूबर को किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि कोरोना की वजह से 11वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय महिला जूनियर हॉकी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन पहले स्थगित किया जा चुका है। पहले इस प्रतियोगिता का आयोजन 3 से 12 अप्रैल तक सिमडेगा ज़िले में ही निर्धारित था।
- वर्तमान में कोरोना के गिरते हुए मामलों के बीच हॉकी इंडिया ने इस चैंपियनशिप का आयोजन कराने का निर्णय लिया है।
- गौरतलब है कि मार्च, 2021 में सिमडेगा में ही राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन बहुत ही भव्य और शानदार तरीके से हुआ था।

गिरिडीह ज़िले को सोलर सिटी बनाने का प्लान

चर्चा में क्यों ?

- 14 सितंबर, 2021 को झारखंड कैबिनेट द्वारा 17 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई, जिसमें गिरिडीह में सोलर सिटी बनाने के अतिरिक्त खनन इलाकों में सड़क पर चलने वाले वाहनों पर टोल टैक्स लगाने जैसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव स्वीकृत किये गए।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- गिरिडीह ज़िला पारसनाथ पर्यटन स्थल होने के कारण झारखंड में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।
- झारखंड के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने गिरिडीह का सोलर सिटी के रूप में चयन करते हुए 80.75 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है।
- इस परियोजना में केंद्र व राज्यों का हिस्सा क्रमश: 40 व 60 प्रतिशत होगा।
- राज्य के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को 3.75 करोड़ रुपए अनुदान की स्वीकृति दी गई है।
- इसके तहत 3 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले परिवारों को 100 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रावधान है।
- रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो एवं देवघर का चयन दूसरे चरण में सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के लिये हुआ है।

22 ज़िलों के पुलिस थानों में ई-एफआईआर को कैबिनेट की मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

- 14 सितंबर, 2021 को राज्य कैबिनेट समन्वय विभाग की सचिव वंदना दादेल ने बताया कि राज्य मंत्रिमंडल ने 22 ज़िलों में ई-एफआईआर पुलिस स्टेशन स्थापित करने को मंज़ूरी दे दी है, इससे लोग थानों का दौरा किये बिना एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

प्रमुख बिंदु

- महिला एवं बाल अपराध, चोरी, सेंधमारी एवं नाबालिगों की गुमशुदगी की शिकायतों से संबंधित विशेष प्रकृति के मामले बिना थाने गए दर्ज कराए जा सकते हैं।
- ऐसे मामलों से संबंधित प्राथमिकी नागरिक पोर्टल या मोबाइल ऐप के माध्यम से दर्ज की जा सकेगी। इसके लिये रामगढ़ और खूंटी को छोड़कर सभी 22 ज़िलों में ई-एफआईआर थाने स्थापित किये जाएंगे।
- सरकार के प्रस्ताव के अनुसार ई-एफआईआर पुलिस थाने प्रत्येक ज़िले में पहले से कार्यरत् कंपोजिट कंट्रोल रूम में कार्य करेंगे।
- केवल डीएसपी या इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को ही ई-एफआईआर थाने के प्रभारी की अतिरिक्त कमान दी जाएगी।

सिंहभूम के गुड़ाबांदा में मिला 'पन्ना'

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा किये जा रहे सर्वेक्षण में पूर्वी सिंहभूम ज़िले के गुड़ाबांदा में 25 वर्ग किमी. के दायरे में पन्ने का भंडार होने का अनुमान है।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि जीएसआई द्वारा 7 सितंबर, 2021 से ड्रोन द्वारा सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसमें गुड़ाबांदा व ठरकूगोड़ा स्थित चावरी बुरु पहाड़ियों में पन्ना मिलने की संभावना व्यक्त की गई है।
- पन्ना हरे रंग का बेरिल खनिज परिवार का एक बहुमूल्य रत्न है। चूंकि इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है, इसलिये इसका उपयोग ज्योतिष के दृष्टिकोण से आभूषणों के रूप में किया जाता है।

सोहराई व कोहबर चित्रकला

चर्चा में क्यों ?

- 17 सितंबर, 2021 को झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रांची स्थित राजभवन में डाक विभाग द्वारा सोहराई एवं कोहबर चित्रकला पर जारी एक विशेष लिफाफे का लोकार्पण किया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- सोहराय व कोहबर कला झारखंड की दो मुख्य लोककला है। यह दोनों चित्रकला मानव सभ्यता के विकास को दर्शाती है।
- इन दोनों चित्रकला में नैसर्गिक रंगों का उपयोग किया जाता है। यह कला हजारीबाग और चतरा में मुख्य रूप से ज़्यादा प्रचलित है।
- झारखंड के अनेक ज़िलों में कोहबर एवं सोहराई की समृद्ध परंपरा रही है। संभवत: आज की कोहबर कला झारखंड में पाए जाने वाले सदियों पुराने गुफाचित्रों का ही आधुनिक रूप है। हजारीबाग के कोहबर चित्रकला के चितेरे मुख्यत: आदिवासी हैं।
- मिट्टी की दीवारों पर बनाए जाने वाले चित्रण महिलाओं द्वारा बनाए गए हैं। यह चित्रण बहुत ही कलात्मक और इतने स्पष्ट होते हैं कि आसानी से पढ़े जा सकते हैं।
- कोहबर के चित्रों का विषय सामान्यत: प्रजनन, स्त्री-पुरुष संबंध, जादू-टोना होता है, जिनका प्रतिनिधित्व पत्तियों, पशु-पक्षियों, टोने-टोटके के ऐसे प्रतीक चिह्नों द्वारा किया जाता है, जो वंश वृद्धि के लिये प्रचलित एवं मान्य हैं, जैसे- बाँस, हाथी, कछुआ, मछली, मोर, कमल या अन्य फूल आदि। इनके अलावा शिव की विभिन्न आकृतियों और मानव आकृतियों का प्रयोग भी होता है। ये चित्र घर की बाहरी अथवा भीतरी दीवारों पर पूरे आकार में अंकित किये जाते हैं।
- हजारीबाग ज़िले के जोरकाठ, इस्को, शरिया, सहैदा, ढेठरिगे, खराटी, राहम आदि गाँवों में कोहबर चित्रांकन सदियों से होता आ रहा है।
- सोहराई चित्रों में दीवारों की पृष्ठभूमि मिट्टी के मूल रंग की होती है। उस पर कत्थई राल, गोद (कैओलीन) और काले (मैंगनीज) रंगों से आकृतियाँ' बनाई जाती हैं। कोहबर एवं सोहराई चित्रों में विभिन्न आदिवासी समूह या उपजाति के अनुसार, थोड़ी भिन्नता पाई गई है।

डालमा हिल में 'पाइथन' का संरक्षण

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में राज्य वन विभाग द्वारा डालमा वन्यजीव अभयारण्य में पाइथन समेत साँपों की अन्य प्रजातियों के संरक्षण की पहल की गई है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि भारत में पाइथन की तीन प्रजातियाँ पाई जाती हैं-
  - इंडियन रॉक पाइथन
  - बर्मीज पाइथन
  - रेटिकुलेटेड पाइथन
- इंडियन पाइथन, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की सूची-I के तहत संरक्षित किया गया है। ऐसे में पाइथन के संरक्षण के लिये राज्य वन विभाग द्वारा पाइथन के आवासों की पहचान करने के साथ-साथ ग्रामीण लोगों को मानव-वन्यजीव संघर्ष से बचने संबंधी उपायों के संबंध में जागरूक किया जा रहा है।
- जमशेदपुर स्थित डालमा वन्यजीव अभयारण्य हाथियों के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ पाए जाने वाले अन्य जीवों में बार्किंग डियर, स्लॉथ बियर एवं विविध सरीसृप प्रजातियाँ उल्लेखनीय हैं।
- गौरतलब है कि वर्ष 2017 में गोवा के हर्पेटोलॉजिस्टक निर्मल कुलकर्णी द्वारा भारतीय पाइथन प्रजातियों के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिये 'लिविंग विथ पाइथन' नामक राष्ट्रव्यापी पहल प्रारंभ की गई थी।

कोल इंडिया लिमिटेड का पहला व्यावसायिक कोल बेड मीथेन निष्कर्षण

चर्चा में क्यों ?

- 20 सितंबर, 2021 को झारखंड के धनबाद में कोल इंडिया की सब्सिडियरी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) एवं प्रभा एनर्जी प्रा. लि. (PEPL) के बीच पहले व्यावसायिक कोल बेड मीथेन के निष्कर्षण हेतु एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया गया।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- अनुबंध के तहत PEPL द्वारा झरिया कोल फील्ड्स के झरिया कोल बेड मीथेन ब्लॉक-1 के डेवलपर रूप में कार्य किया जाएगा।
- सेंट्रल माइन प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट (CMPDI) इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिये प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी (PIA) है।
- यह निष्कर्षण कोल इंडिया द्वारा मीथेन उत्सर्जन में कमी लाने के लिये किये जा रहे प्रयासों का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त कोयला खनन से पहले सीबीएम (कोल बेड मीथेन) निष्कर्षण करने से कोयला खदानों में खनन के समय विस्फोट एवं आगजनी की घटनाओं में कमी आएगी, जिससे भूमिगत कोयला खदानों में काम करने वाले क्रमिकों की सुरक्षा बढ़ जाएगी।
- इसके अलावा सीबीएम का निष्कर्षण ऊर्जा के उपयोग को भी सक्षम करेगा, जो खनन के दौरान निकलकर बर्बाद हो जाता है।
- उल्लेखनीय है कि सीबीएम प्राकृतिक गैस का एक रूप है, जिसे कोयला निक्षेपों से प्राप्त किया जाता है। यह ऊर्जा का एक गैर-परंपरागत स्रोत है, जिसका उपयोग विभिन्न देशों में सीमेंट, रोलिंग मिल, स्टील प्लॉन्ट्स आदि उद्योगों में किया जा रहा है।

झारखंड की सभी पंचायतों में जेनरिक मेडिकल स्टोर्स खोलने का प्रस्ताव

चर्चा में क्यों ?

- 21 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने औषधि निदेशालय को राज्य की सभी पंचायतों में जेनरिक मेडिकल स्टोर्स खोलने का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया।

प्रमुख बिंदु

- इन जेनरिक मेडिकल स्टोर्स पर होने वाले खर्च का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के फंड से किया जाएगा। औषधि निदेशालय की ओर से मेडिकल स्टोर्स खोलने के प्रस्ताव पर अभियान निदेशक एनएचएम की सहमति भी ली जाएगी।
- जेनरिक मेडिकल स्टोर्स के खुल जाने से राज्य की प्रत्येक पंचायतों में छोटे-मोटे मर्ज़, बुखार, जुकाम, खाँसी, दस्त आदि की दवाओं के लिये ग्रामीणों को भटकना नहीं होगा।
- पंचायत में खुलने वाले इन जेनरिक स्टोर्स में करीब 100 प्रकार की दवाएँ होंगी। ये दवाएँ मरीज़ों को मुफ्त में मिलेंगी।
- इन स्टोर्स के संचालन के लिये फार्मासिस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। वैसी दवाएँ ही रखी जाएंगी, जो प्रशिक्षण के बाद पंचायत स्तर के स्वास्थ्य अधिकारी दे पाएंगे। ऐसी दवाओं की सूची औषधि प्रशासन की ओर से तैयार की जा रही है।
- जन औषधि केंद्र के लिये मिलने वाली दवाएँ भी पंचायत स्तर पर खुलने वाले इन मेडिकल स्टोर्स पर मिलेंगी। इसका संचालन पंचायत प्रतिनिधियों के अधीन होगा। इसका निरीक्षण समय-समय पर सिविल सर्जन और ज़िला अधिकारी करेंगे।
- गौरतलब है कि राज्य में कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 4402 है। इनके अधीन 32,623 गाँव आते हैं। कई बार मलेरिया, डायरिया आदि से पीड़ित मरीज़ों को समय पर दवाएँ नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण मरीज़ों की मौत हो जाती है। ऐसे में अगर स्वास्थ्य विभाग का यह प्रस्ताव राज्य सरकार मंज़ूर कर लेती है तो ग्राम पंचायत में ही छोटे-मोटे मर्ज़, बुखार, जुकाम, खाँसी, दस्त आदि का समुचित उपचार हो पाएगा।

सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दुमका से 'सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना' की शुरुआत की।

प्रमुख बिंदु

- इस योजना के तहत जनवितरण प्रणाली दुकानों से लाभार्थियों को 10 रुपए में वर्ष में दो बार एक साड़ी एवं लुंगी या धोती वितरित की जाएगी।
- इस योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित राशन कार्डधारकों को मिलेगा। योजना में शामिल व्यक्तियों द्वारा राशन कार्ड के साथ-साथ सरकार द्वारा निर्गत पहचान-पत्र, जैसे- आधार कार्ड, मतदाता पहचान-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, मुखिया या वार्ड पार्षद द्वारा अनुशस्ति-पत्र को दिखाकर योजना का लाभ उठाया जा सकता है।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि इस योजना की शुरुआत पहली बार वर्ष 2014 में की गई थी, जिसका क्रियान्वयन वर्ष 2015 में रोक दिया गया था।
- वर्ष 2020 में सरकार द्वारा झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के कार्यान्वयन को स्थगित कर उसकी जगह नई योजना 'सोना-सोबरन धोती-साड़ी योजना' प्रारंभ करने की घोषणा की गई।

जेएसएलपीएस (JSLPS) द्वारा पीवीटीजी (PVTGs) जनजातियों के विकास की पहल

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी (JSLPS) द्वारा आजीविका सुधार के माध्यम से राज्य के विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTGs) को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिये गैर-सरकारी संगठन 'वासन' के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किये गए।

प्रमुख बिंदु

- इस समझौते के अनुसार वासन, JSLPS द्वारा संचालित 'उड़ान' प्रोजेक्ट के अंतर्गत PVTGs की आजीविका सुधार के लिये उनको शहद की उन्नत खेती से जोड़कर उनकी आय में वृद्धि का प्रयास किया जाएगा।
- इस परियोजना के तहत JSLPS द्वारा झारखंड बाजरा मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें वासन द्वारा बाजरा उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण विपणन आदि तक तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
- साथ ही राज्य के 20 पिछड़े प्रखंडों में बैकयार्ड पॉल्ट्री के माध्यम से उद्यमिता का मॉडल स्थापित कर PVTGs की आय में वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या में से 26.2% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। इसमें से कुछ जनजातियों PVTGs का दर्जा प्रदान किया गया है, जैसे- असुर, बिरहोर, बिर्जिआ, पहाड़ी खारिया, कोरवा, माल पहाड़िया, परहिया आदि।

झारखंड के 9 दिव्यांगों को हुनरबाज़ पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- 25 सितंबर, 2021 को आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आयोजित ऑनलाइन कार्यक्रम में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा झारखंड के 9 दिव्यांग युवाओं को 'हुनरबाज़ पुरस्कार' से सम्मानित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- गौरतलब है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना एवं स्व-रोज़गार प्रशिक्षण संस्थान का 'हुनरबाज़ पुरस्कार' ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, हैदराबाद द्वारा संस्थापित किया गया है।
- अंत्योदय दिवस (25 सितंबर) के अवसर पर 15 राज्यों के 75 दिव्यांगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें झारखंड से कुलवंती बाड़ा (गढ़वा), शबनम खातून एवं सुनीता ताटुडू (हज़ारीबाग), सावित्री (दुमका), आशा टूटी (खूँटी), अबोध महाथा और तेजीय कुमारी (बोकारो), पिंकी (धनबाद), नेहा रेखा कुमारी (राँची) शामिल हैं।

प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिये आदिवासी भाषाओं में पाठ

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में झारखंड के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अगले शैक्षणिक सत्र के बाद आदिवासी भाषाओं में कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के छात्रों को पाठ पढ़ाने का एक नया मॉडल पेश करने के लिये 5,600 से अधिक सरकारी प्राथमिक स्कूलों की पहचान की है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद (जेईपीसी) के अनुसार, इस परियोजना के लिये केवल उन स्कूलों को चुना गया है, जहाँ बड़ी संख्या में छात्रों ने आदिवासी भाषाओं का इस्तेमाल अपनी पहली भाषा के रूप में किया है।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के राज्य समन्वयक अभिनव कुमार ने कहा कि राज्य पहले ही ऐसे छात्रों के लिये आदिवासी भाषाओं (संथाली, मुंडारी, कुडुक) में पाठ्यपुस्तकें पेश कर चुका है और शिक्षा का नया मॉडल इन पुस्तकों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि एक बार जब छात्र उस भाषा में मूल बातें समझ जाते हैं, जिसमें वे अधिक सहज महसूस करते हैं, तो शिक्षा का माध्यम धीरे-धीरे हिन्दी या अंग्रेज़ी में बदल दिया जाएगा।
- उन्होंने कहा कि आदिवासी भाषाओं में छात्रों के एक समूह को शिक्षित करने का नया मॉडल छात्रों की पढ़ाई में रुचि विकसित करने और उन्हें अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा।
- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, आदिवासी समुदाय झारखंड की कुल 3.29 करोड़ की आबादी का कम-से-कम 26.3 प्रतिशत है।
- शिक्षा के नए मॉडल के तहत किसी विशेष क्षेत्र में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली आदिवासी भाषा का इस्तेमाल उस क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के रूप में किया जाएगा। उदाहरण के लिये, संथाली भाषा आमतौर पर झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में उपयोग की जाती है, जबकि मुंडारी आमतौर पर कोल्हान में बोली जाती है, जिसमें पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम ज़िले शामिल हैं।
- जेईपीसी के प्रवक्ता ने कहा कि कक्षा 1 के छात्रों को पूरा पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा, ताकि वे विषयों को समझ सकें। हालाँकि कक्षा 2 में केवल 60% पाठ्यक्रम स्थानीय भाषा में और शेष 40% अंग्रेज़ी या हिन्दी में कवर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने 'वैक्सीन एक्सप्रेस' वाहनों को दिखाई हरी झंडी

चर्चा में क्यों ?

- 28 सितंबर, 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोविड-19 टीकाकरण अभियान को गति देने के उद्देश्य से केयर इंडिया के समर्थन में कोविड-19 वैक्सीन ड्राइव (वैक्सीन एक्सप्रेस) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अधिक-से-अधिक लोगों का टीकाकरण करने के लिये केयर इंडिया के सहयोग से राज्य में टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इसी के तहत राज्य के विभिन्न ज़िलों में 60 मोबाइल टीकाकरण वैन भेजी जा रही हैं।
- ये सभी वैन टीकाकरण अभियान को जन-जन तक पहुँचाने के लिये 'टीका एक्सप्रेस' के रूप में काम करेंगी।
- इन 'वैक्सीन एक्सप्रेस' की मदद से लोगों के लिये वैक्सीन प्राप्त करना आसान हो जाएगा। यह सुविधा लोगों को उनके घरों पर ही मिलेगी।
- सोरेन ने कहा कि अब तक राज्य भर में 1 करोड़ 70 लाख से अधिक लोगों को कोविड-19 के वैक्सीन की पहली खुराक और करीब 40 लाख लोगों को दूसरी खुराक मिल चुकी है।

कैबिनेट ने कांटाटोली फ्लाईओवर को मंज़ूरी दी

चर्चा में क्यों ?

- 28 सितंबर, 2021 को राज्य मंत्रिमंडल ने 224.94 करोड़ रुपए की लागत से कोकर में योगदा सत्संग से शांतिनगर को जोड़ने वाले 2240 मीटर लंबे कांटाटोली फ्लाईओवर के निर्माण के लिये मंज़ूरी दे दी।

प्रमुख बिंदु

- कैबिनेट सचिव वंदना डडेल ने बताया कि इस परियोजना का उद्देश्य राँची के कांटाटोली क्षेत्र में सड़क के बुनियादी ढाँचे में सुधार करना है।
- राँची शहर के भीतर विभिन्न इलाकों को जोड़ने में कांटाटोली एक रणनीतिक बिंदु है। यह जमशेदपुर, हज़ारीबाग, पटना और क्षेत्र के अन्य महत्त्वपूर्ण शहरों की सड़क माध्यम से यात्रा करने वाले लोगों के लिये एक महत्त्वपूर्ण पारगमन बिंदु है।

नोट :

- इसके साथ ही कैबिनेट ने चावल फोर्टिफिकेशन योजना के तहत फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने के लिये एक पायलट परियोजना शुरू करने को भी मंज़ूरी दी।
- इसके अलावा कैबिनेट ने शहर के भीतर जलापूर्ति की प्रक्रिया को आसान बनाने के उद्देश्य से शहरी जलापूर्ति सुधार परियोजना के तहत कोडरमा ज़िले में झुमरी तिलैया के लिये एक जलापूर्ति परियोजना को भी मंज़ूरी दी।
- इसी तरह राज्य मंत्रिमंडल ने कांके में 113 करोड़ रुपए से अधिक के एक ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना को अपनी मंज़ूरी दी, जिसका उद्देश्य अन्य ज़िलों और राज्यों से प्रवेश करने वाले भारी ट्रकों को नो-एंट्री अवधि के दौरान पार्क करने और माल उतारने के लिये जगह प्रदान करना है। यह झारखंड का पहला परिवहन नगर होगा।

झारखंड को गोवा से मिला ट्रेन कनेक्शन

चर्चा में क्यों ?

- 28 सितंबर, 2021 को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जासीडीह (झारखंड)- वास्को डी गामा (गोवा) ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसी के साथ झारखंड का गोवा के साथ सीधा ट्रेन कनेक्शन हो गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह ट्रेन धनबाद, बोकारो और राँची से होकर गुज़रेगी। यहाँ से गोवा पहुँचने में करीब 48 घंटे लगेंगे।
- गोवा के अलावा यह लोगों को ओडिशा, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना तक भी पहुँचने में मदद करेगी।

The Vision

नोट :